भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **3453**
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

विदेशी ऋण और माल व्यापार घाटे का आकलन

3453. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2026 की पहली तिमाही के दौरान भारत के विदेशी ऋण के 762.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने और अल्पकालिक ऋण के सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.0 प्रतिशत तक बढ़ने से उत्पन्न वित्तीय जोखिमों का विश्लेषण किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर 70.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात को ध्यान में रखते हुए, जून, 2026 में माल व्यापार घाटे के वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के फलस्वरूप 30.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का भारतीय रुपये की स्थिरता के संबंध में प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बढ़ते व्यापार घाटे से उत्पन्न जोखिमों से निपटने के लिए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किए जा रहे समन्वित उपायों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) मार्च 2026 के अंत में, भारत का विदेशी ऋण 762.8 अमेरिकी बिलियन डॉलर था और जीडीपी के लिए अल्पकालिक विदेशी ऋण का अनुपात 4.1% था।.

प्रमुख विदेशी ऋण भेद्यता संकेतक स्थिर बने हुए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि भारत का विदेशी ऋण स्तर सतत और विवेकपूर्ण रूप से प्रबंधित है। मार्च 2026 के अंत में, भारत का विदेशी ऋण-जीडीपी अनुपात 20.8 प्रतिशत था। कुल विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 90.6 प्रतिशत रहा, जबकि अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता) कुल विदेशी ऋण का 19.6 प्रतिशत था। ऋण सेवा अनुपात मार्च 2025 के अंत में 6.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2026 के अंत में 5.8 प्रतिशत हो गया।.

(ख) और (ग) सरकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास और भारत के बाहरी क्षेत्र के लिए उनके प्रभावों की लगातार निगरानी करती है। भारतीय रुपये (आईएनआर) की विनिमय दर विभिन्न घरेलू और वैश्विक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे कि डॉलर सूचकांक में उत्तार -चढ़ाव, पूंजी प्रवाह में रुझान, ब्याज दरों का स्तर, कच्चे तेल की कीमतों में उत्तार-चढ़ाव, चालू खाता घाटा, आदि। इसलिए, वस्तु व्यापार घाटा केवल उन कारकों में से एक है जो भारतीय रुपये (आईएनआर) की विनिमय दर को प्रभावित कर सकता है।
बेहतर प्रतिस्पर्धा, बाजार पहुंच और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ गहरे एकीकरण के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करके महत्वपूर्ण आयात निर्भरता को कम करने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक व्यापक रणनीति भी अपनाई है।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 को लागू कर रही है, जो निर्यात विविधीकरण, बाजार तक पहुंच, व्यापारिक सुगमता , डिजिटलीकरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण पर केंद्रित है। भारत ने सभी क्षेत्रों में अपने व्यापार संबंध और कई मुक्त व्यापार समझौतों का भी काफी विस्तार किया है। साथ ही, सरकार अवसरंचना, रसद (लोजिस्टिक्स) और व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) में उच्च निवेश के माध्यम से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत कर रही है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय रसद नीति, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा (कॉरीडोर) विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी), एसडब्ल्यूआईएफटी के माध्यम से सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, और व्यापार सुविधा में सुधार रसद (लोजिस्टिक्स) लागत को कम कर रहे हैं और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) और मेक इन इंडिया योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (रेजीलिएंस) बढ़ाया जा रहा है। कार्यनीतिक आयात निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमता निर्माण को बढ़ावा दे रही है, प्रौद्योगिकी अपनाने और नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन (रेजीलिएंस) को मजबूत कर रही है, कच्चे तेल, उर्वरकों और महत्वपूर्ण खनिजों जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए आयात स्रोतों में विविधता ला रही है और अक्षय ऊर्जा और अन्य उभरते क्षेत्रों में निवेश में तेजी ला रही है।
भारत पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भी बनाए हुए हैं, जो बाहरी क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने में सहयोग देता है।

***